an>

Title: Regarding the issue of water management in the country.

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सभापति महोदय, इस देश की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जनसंख्या बढ़ने के साथ खाने, फूड सिक्युरिटी और पीने के पानी पर दबाव आ रहा है। कभी बाढ़, कभी सुखाड़ के कारण किसान को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि पानी का विषय कई राज्यों के साथ बंटा हुआ है। लेकिन हम जब भी केन्द्र सरकार से कोई मांग करते हैं तो उसके आधार पर वह कहती है कि यह राज्य का विषय है और राज्य कनकरैंट सूची होने के कारण हम बहुत कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं होते। आपको पता है कि ज्यादातर डिसप्यूट जल के कारण ही है।

अभी सरकार ने इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी के तौर पर कई जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग की तरह नेविगेशन के लिए घोषित किया है। यही हालत जब ग्रामीण सड़कों की थी तो पीएमजीएसवाई की योजना बनी। उसमें केन्द्र सरकार ने कहा कि राज्य नहीं करेगा, केन्द्र उस योजना को पूरा करेगा। आज पीएमजीएसवाई बड़ी सक्सैसफुल योजना है। मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से यही आग्रह है कि जिस तरह जनसंख्या, पीने के पानी का दबाव आ रहा है, उसके लिए फूड सिक्युरिटी एक्ट में लोगों को खाना देना है, यह केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि पीएमजीएसवाई के तौर पर ही वह एक पूरा सीएमसीपीएल बनाए। जिस तरह का कोर नेटवर्क उसने रोड का बनाया था, उसी तरह पूरे जल का बनाए और अपने खर्चे से 60:40, 90:10 के आधार पर या 100 प्रतिशत फंडिंग देते हुए यदि यह काम करेगी तो हम इरीगेशन के एरिया को बढ़ा पाएंगे। यदि खेती के एरिया को बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर फसल आएगी और किसान समृद्ध होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द, जय भारत।

HON. CHAIRPERSON:

Shri Bhairon Prasad Mishra and

Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri Nishikant Dubey.